

57



आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan, रस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road, राजकोट / Rajkot - 360 001



Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com

रजिस्टर्ड डाक ए. डी. द्वारा :-

क	अपील / फाइल संख्या Appeal / File No.	मूल आदेश नं / O.O. No.	दिनांक / Date
	V2/276/RAJ/2016	DC/JAM/ST/06/2015-16	30.10.2015

6513 to 6516

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

RAJ-EXCUS-000-APP-143-2017-18

आदेश का दिनांक / 18.12.2017 जारी करने की तारीख / 20.12.2017
Date of Order: Date of issue:

कुमार संतोष, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /
Passed by Shri Kumar Santosh, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ आयुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवाकर, राजकोट / जमनगर / गण्डीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सूचित /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise / Service Tax, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name&Address of the Appellants & Respondent :-
M/s. Momai Enterprise, Bhogat, Tal: Jam Kalyanpur, Dist : Devbhoomi Dwarka

इस आदेश(अपील) से व्यक्ति निम्नलिखित तरीके से उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील टापर कर सकते हैं।
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अन्तर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अन्तर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण सूत्रांक से संबंधित जारी आदेशों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, को भी जानी चाहिए।
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बतलाए गए अपील के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहामली भवन असावा अहमदाबाद- 380016 को भी जानी चाहिए।
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asawa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमवली, 2001, के नियम 6 के अन्तर्गत सिस्टट किराई एवं फॉर्म EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की सीमा 5 लाख की सीमा और लगाया गया जर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपए, 5,000/- रुपए अथवा 10,000/- रुपए का सिस्टट जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। सिस्टट शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के पास से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्रफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्रफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। संलग्न आदेश (एट ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का सिस्टट शुल्क जमा कराया होगा।
The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अन्तर्गत सेवाकर नियमवली, 1994, के नियम 9(1) के तहत सिस्टट फॉर्म ST-5 में चार प्रतियों में की जा सकती एवं उसके साथ जिन आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की सीमा 5 लाख की सीमा और लगाया गया जर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपए, 5,000/- रुपए अथवा 10,000/- रुपए का सिस्टट जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। सिस्टट शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के पास से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्रफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्रफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। संलग्न आदेश (एट ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का सिस्टट शुल्क जमा कराया होगा।
The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is upto 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees. in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is upto 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees. in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

(i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धारा (2) एवं (2A) के अंतर्गत दाने की गयी अपील, सेलक्टर नियमावली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित फॉर्म S.T.-7 में की जा सकती एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा जारी आदेश की प्रतियाँ संलग्न करे (जिसमें से एक प्रति प्रस्तुतित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा लगाए गए आयुक्त अथवा आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेलक्टर, को अपील न्यायाधिकरण को अर्पण करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

(ii) शीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेलक्टर अपील न्यायाधिकरण (सेल्टोर) के प्रति अपील के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एन के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेलक्टर को भी लागू की गई है, इसे आदेश के प्रति अपील न्यायाधिकरण में अपील करने समय उत्पाद शुल्क/सेलक्टर कर मूल्य के 10 प्रतिशत (10%), जब मूल एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि इस बंधन तथा से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेलक्टर के अंतर्गत 'जब किंग गण शुल्क' में निम्न शामिल है

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत कर
- (ii) सेल्टोर जमा की गई राशि
- (iii) सेल्टोर जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय कर

- बशर्त यह कि इस धारा के प्राधान्य वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के अंतर्गत से पूर्व किसी अपील न्यायाधिकरण के समस्त विचारणीय स्थान अर्थात् अपील को लागू नहीं होगी।

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C) भारत सरकार की पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India:

इस आदेश की पुनरीक्षण अधिकृत विभागीय अधिकृत मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम पैराग्राफ के अंतर्गत जमा कर, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इकाई, वित्त मंत्रालय, राजमंत्र भवन, पार्सी मजिस्ट्रेट, जौहान टीप भवन, संसद भवन, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35E ibid

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35E ibid

(i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के परिवहन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह परिवहन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के परिवहन के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के स्थानों में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of an excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India

(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(iv) अधिनियम उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो इच्छा के लिए इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मूल्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (सं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा निर्यात की गई तारीख अथवा समावृत्ति पर या बाद में प्रस्तुत किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां फॉर्म संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संघर्ष के 3 महीने के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अद्यतनी के साथ, के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the O.I.O and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ विभागीय अधिकृत निर्धारित शुल्क की अद्यतनी की जानी चाहिए। जहाँ संलग्न कर एक लाख रुपये या उससे कम है तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न कर एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। / The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपरोक्त इन से किया जाना चाहिए। इस तथ्य के होते हुए भी की निम्न वर्गीकृत करों से बचने के लिए यथास्थिति अपील न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.

(E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थान आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O, as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs. 6.50 as prescribed under Schedule-1 in terms of the Court Fee Act,1975, as amended.

(F) शीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेलक्टर अपील न्यायाधिकरण (बार्डर थिफि) नियमावली, 1982 में उल्लिखित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्बन्धित करने वाले विषयों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(G) उपर अपील न्यायाधिकरणों को अपील दर्जित करने से संबंधित विवरण, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपील न्यायाधिकरण वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in

53

:: ORDER - IN - APPEAL ::

M/s. Momai Enterprise, At: Bhogat, Taluka: Jam Kalyanpur, Dist. Devbhumi Dwarka (hereinafter referred to as "the appellant") filed this appeal, against Order-in-Original No. DC/JAM/ST/06/2015-16 dated 30.10.2015/03.11.2015 (hereinafter referred to as "the impugned order") passed by the Deputy Commissioner, Central Excise Division, Jamnagar (hereinafter referred to as "the lower authority").

2. The brief facts of the case are that the appellant is holding Service Tax registration No. AELPL1589ASD001 for providing services falling under various taxable categories viz. "Manpower Recruitment or Supply Agency Service", "Construction services other than residential complex, including commercial/ industrial buildings or civil structures", "Transport of Goods by road/ transport agency service" and "Supply of tangible goods service". Intelligence revealed that the appellant was providing services to their clients and collecting Service Tax but not paying the same to the exchequer. The data received of ACES system confirmed that the appellant had not deposited Service Tax after August, 2011. Therefore, inquiry was initiated against the appellant, who submitted all invoices issued by him for the period from 2010-11 to 2012-13, which suggested that the appellant had also carried out excavation and filling work for some of his customers classifiable under "Site formation and clearance, excavation and earthmoving and demolition" services in addition to providing manpower to various customers. The appellant was charging Service Tax from 2010-11 and paid Service Tax of Rs. 1,22,967/- vide challan dated 05.03.2011 and Rs. 53,989/- vide challan dated 11.08.2011 against the Service Tax liability of Rs. 6,38,667/- for the period from 2010-11 to 2012-13 resulting into short payment of Service Tax of Rs. 4,61,689/-.

3. Show Cause Notice No.IV/15-02/ST/ADJ/2013 dated 13.01.2014 was issued to the appellant demanding Service Tax of Rs. 4,61,689/-including Education cess and Secondary & Higher Education Cess and since the appellant had tendered a cheque of Rs. 4,00,000/- voluntarily, which was deposited into government account, it was proposed to appropriate the same against their Service Tax liability and interest. Late fee of Rs. 2,000/- / Rs. 20,000/- was also proposed to be recovered in the Show Cause Notice in addition to imposing penalty under Section 76, 77 and 78 of the Finance Act, 1994 (hereinafter referred to as "the Act") upon them.



52

3.1 The said Show Cause Notice was adjudicated by the lower adjudicating authority vide impugned order wherein he confirmed Service Tax of Rs. 4,61,689/- including Education cess and Secondary & Higher Education Cess and ordered to appropriate of Rs. 4,00,000/- paid by the appellant and ordered to recover the balance amount. He also ordered to recover interest under Section 75 of the Act, late fees of Rs. 60,500/- under Section 70 of the Act and imposed penalty of Rs. 10,000/- under Section 77 of the Act and penalty of Rs. 4,61,689/- under Section 78 of the Act with an option to pay reduced penalty as per Section 78 of the Act. The lower adjudicating authority does not impose any penalty under Section 76 of the Act.

4. Being aggrieved with the impugned order, the appellant preferred the present appeal on the grounds that the lower adjudicating authority failed to consider the submission made by them; that the department has taken highest value out of invoice value, balance sheet value and value shown in Form 26AS resulting into double taxation; that the basis on which value of service provided by them has been arrived at by the department is not correct; that the findings of the lower adjudicating authority are not correct; that ignorance is not equivalent to suppression of fact and relied on the judgment in the case of Bright Security Services & Labour Contr. reported as 2012 (26) STR 342 (Tri.-Bang.), R. Deivendran reported as 2009 (15) STR 256 (Tri.-Chennai); that intention to evade payment of duty is not mere failure to pay duty. It must be something more than that i.e. the assessee must be aware that duty was leviable and he must have deliberately avoided payment of duty and they relied on the decision in the case of Tamilnadu Housing Board reported as 1994 (74) ELT 9 (SC); that no penalty can be imposed when no intention to evade payment of duty as held in the case of SVM Nett Project Solutions Pvt Ltd reported as 2010 (17) STR 298 (Tri.-Bang.); that they have discharged Service Tax liability before issuance of Show Cause Notice.

5. Shri Vikas Mehta, Consultant appeared for personal hearing wherein he reiterated the grounds of appeal and application for condonation of delay; that they have strong merit if condonation is granted; that the reason for delay is beyond their control, the appellant being from village and very small proprietorship firm.



FINDINGS:

6. I have carefully gone through the impugned order, appeal memorandum and written as well as oral submissions made by the appellant. The issue to be decided in the appeal is whether the appellant is liable to pay differential Service Tax, interest and penalties or not.


7. I find that the present appeal has been filed by the appellant on 20.12.2016 in respect of the impugned order issued on 30.10.2015. The appellant in Form ST-4 has mentioned the receipt of the impugned order by them on 09.11.2015, which establishes that the appeal has been filed after 407 days from the date of receipt of the impugned order by the appellant. The appellant has filed an application for condonation of delay by stating the reason that sine he is living in a small village and not having knowledge of law and procedure to file an appeal and due to non availability of a reputed consultant/ advocate and they have now approached the consultant and hence delay occurred and requested to condone the delay.

7. In light of the above facts, I find that the appeal first needs to be decided on the limitation of time. I find that the appeal has been filed beyond 90 days of the receipt of the impugned order. The Commissioner (Appeals), as per proviso to Section 83(3A) of the Act, is vested with power to condone delay of maximum up to thirty days, over and above the normal period of sixty days, on reasonable cause being shown. The present appeal is filed beyond stipulated time limit of 90 days provided under the statute. I find no reason to entertain such an appeal beyond stipulated time limit in the law. Therefore, I am of the considered view that such an appeal is liable to be dismissed on the ground of limitation of time alone. Accordingly, I reject the present appeal on the ground of limitation of time in filing appeal.

8. In view of above facts and legal position, I reject the present appeal being time barred and uphold the impugned order.

९. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

9. The appeal filed by the appellant stands disposed off in above terms.


(कुमार संतोष)
आयुक्त (अपील्स)